SCH-USY/3.00/2O

श्री शरद यादव (क्रमागत) : आपका जो नेशनल एजेंडा है, उसमें आपने जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया है। आप ताज्जुब करेंगे कि वहां एनएचपीसी का जो प्लांट है, उससे जो आमदनी होती है, वह हिन्दुस्तान के बाकी प्लांट्स की कुल आमदनी की आधी होती है। वहां लगभग आठ या नौ प्लांट लगे हुए हैं। आपने अपने Agenda for Alliance में कहा था कि जहां एनएचपीसी के प्लांट्स हैं, वहां आप पानी रोक नहीं सकते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आप सिर्फ बहते हुए पानी से ही लाभ ले सकते हैं और उस बहते हुए पानी से वहां पर हमने आठ-नौ प्लांट बनाकर रख दिए हैं। हिन्दुस्तान में एनएचपीसी से होने वाले कुल लाभ का आधा अकेले जम्मू-कश्मीर से होता है। आपने अपने Agenda for Alliance में यह लिखा हुआ है। वहां की सरकार, वहां के सब लोग लगातार आपसे इसके लिए मांग करते आए हैं, अब तो वहां आपकी सरकार है, लेकिन पहले भी हर सरकार यह मांग करती आई है। वहां की जो माली हालत है, उसको ठीक करने के लिए आप दो या तीन प्लांट दीजिए, आप इसकी शुरुआत तो करिए। वहां की जो जनता है, वह कई तरह के नारे लगा रही है, यह देश के लिए चिंता का सवाल है। दुलहस्ती पॉवर प्लांट है, बुरसर है, सलाल है, उरी है, ऐसे बहुत से पॉवर प्लांट हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन....(व्यवधान)... तो ये कश्मीर का जो मामला है, उसको कहीं न कहीं हम सभी को महसूस करना चाहिए। अभी वहां यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत से लोग गए थे। वे सरकार से और हम सभी लोगों से आग्रह करके कह रहे हैं कि यही वक्त है कि बातचीत करके हमें उनकी समस्याओं का कोई रास्ता

निकालना चाहिए। देश को बनाने के लिए, देश को ठीक रखने के लिए आपको हर तरह के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

कितनी ही तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। चाहे किसी सरकार के समय में ये समस्याएं रही हों, सभी सरकारों ने इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया है, लेकिन सिर्फ इस बार कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। आपने जो सारे का सारा अलायंस किया, इस अलायंस के सामने जितने भी सवाल रखे गए हैं, एक बात पर भी आपने कदम उठाने का काम नहीं किया है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि यही वक्त है, जब सरकार इस दिशा में पहल करे।

आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस दौर में बॉर्डर पर जितना तनाव रहा है और जितने लोग हलाक़ हुए हैं, उतने पहले कभी किसी दौर में नहीं हुए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारी समस्याएं कश्मीर में के हैं। इसलिए कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए हमें चाहे किसी से भी, किसी भी सीमा जाकर बात क्यों न करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। पहले भी हम यह करते आए हैं। यह विकट समस्या है और इसको ठीक करने का हमारे पास यही मौका है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस पूरे के पूरे अभिभाषण में बताया गया है कि इस देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में हर तरह के लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, ट्रेडर्स हैं। इन सबकी अपनी एक आवाज है। अगर कहीं किसी एक तबके की आवाज नहीं है, तो केवल ट्राइबल तबके के लोगों की नहीं है, क्योंकि ट्राइबल्स अकेले हैं, जंगलों में जाकर बस गए हैं, बेज़ुबान हैं। मैं आपसे कहूंगा

कि 10 करोड़ में कोई एक आदमी है, जो आगे बढ़ा है, अन्यथा जिन हालात में वे लोग हैं, उसका बयान करना भी कठिन है। इनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई सामूहिक ताकत नहीं है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हैं। ओडिशा का आदिवासी अलग नाम से जाना जाता है, गुजरात के आदिवासी का अलग नाम है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी का नाम अलग है, इसी तरह मध्य प्रदेश में अलग तरह के आदिवासी बसे हुए हैं। आज़ादी के बाद से हमने इनके लिए शैड्यूल्ड-V और शैड्यूल्ड-VI बना कर रखे हैं, लेकिन आज तक उनको ठीक से लागू नहीं किया गया। 1996 में हमने एक नया कानून बनाया था कि पंचायत के माध्यम से इनको पूरे अधिकार देंगे। याद रखिए, अगर हिन्दुस्तान की संपदा और संपत्ति सबसे ज्यादा कहीं पर संचित है, तो वहां संचित है, जहां हिन्दुस्तान के आदिवासी बसे हुए हैं। ये आदिवासी सतपुड़ा और विंध्याचल की रेंज में बसे हुए हैं। वहां पर सरकार ने उनका एक छोटा सा टाउन बना दिया है, लेकिन केवल इससे उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। (2p/RPM पर जारी)

RPM-USY/2P/3.05

श्री शरद यादव (क्रमागत): इन आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रपति और गवर्नर को अधिकार दिए हुए हैं। मैं राष्ट्रपति जी से आदिवासियों को लेकर मिला और गुजरात के गवर्नर से मिला। गुजरात के गवर्नर से कई बार आदिवासी मिले। यहां हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो उसी इलाके से हैं, जहां भील लोग रहते हैं। वे कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कई दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो हक और हकूक हैं,

वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनकी पंचायत और उनकी काउंसिल को अधिकार था कि कोई भी आदमी बाहर से नहीं आ सकता है। उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता है और कोई भी काम, किसी भी प्रकार का खनन उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन उनकी अनुमति के बिना सब काम जारी हैं। उन्हें भारत सरकार से जो भी पैसा मिलता है, वह उन तक नहीं पहुंचता है।

महोदय, यह हालत केवल गुजरात में ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी यही हालत है। देश की सरकार, यानी भारत सरकार, हिन्दुस्तान के 10 करोड़ आदिवासियों के बारे में और राज्यों की सरकारें भी उनके बारे में ध्यान नहीं देंगी, तो हिन्दुस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें इतने सीधे, इतने बेज़ुबान और जंगल में बसे लोग हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। वे जंगल में बसे हैं। वहीं सबसे ज्यादा सम्पत्ति है। वहीं सबसे ज्यादा खनिज हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तबाही और बरबादी उन्हीं की हो रही है। उनके लिए संविधान में जो कानूनी प्रोटेक्शन दिया गया है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं इस बारे में राष्ट्रपति जी से मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह उनका अभिभाषण है, इसमें भी उन आदिवासियों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस अभिभाषण में शेड्यूल 5 और 6 के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह उनके ऊपर कहीं भी लागू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह देश मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि हिन्दुस्तान का इतना बड़ा तबका आज पूरी तरह से अपने अधिकारों से वंचित है।

महोदय, झारखंड में एक कानून बना और इस बारे में छोटा नागपुर में भी काफी आन्दोलन हुए हैं। वहां जो कानून बना, उसके जरिए वहां के जो आदिवासी हैं, उनकी खेती और जमीन को हड़पने का खेल खेला जा रहा है। मेरे साथी ने मुझे याद दिलाया कि वह आन्दोलन इतना बड़ा हो गया है कि सारी पार्टियां उसमें लगी हुई हैं, लेकिन सरकार बिलकुल अड़ी हुई है कि नहीं, हम तो यह काम करेंगे। आज देश में आदिवासियों के इस तरह के हालात हैं और इस तरह की खराब स्थिति है।

महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या सामाजिक विषमता की है। इस समस्या का समाधान तो हमें ही करना पड़ेगा। जो सोशल डिस्पैरिटी है, उसके चलते ही यह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामाजिक विषमता है, वही सब चीज की जड़ है। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके बाबत तो 'स्टैंड अप' है, 'स्टार्टअप' है, 'मुद्रा' है, 'मेक इन इंडिया' है, 'स्वच्छ भारत' है। इसके लिए तो अनेक काम चल रहे हैं। ये काम केवल यही सरकार नहीं कर रही है, बल्कि इससे पिछली सरकारों ने भी कई बार किए हैं। सब ने किया है , लेकिन भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता उन तक पहुंचती ही नहीं है। उन्हें दिया गया धन पर्कुलेट ही नहीं होता है। इसलिए कि पूरे के पूरे देश की न्याय व्यवस्था में उन आदिवासियों का कोई हिस्सा नहीं है।

महोदय, श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय मंत्री ने जो कानून बनाए, वे नहीं चल पाए। कोलीजियम चल रहा है। मेरा तो यह मानना है कि चाहे आपका सिस्टम है या उनका सिस्टम है, उसमें गरीब की कोई जगह नहीं है। उसे कैसे न्याय मिले? जो सारे देश के न्यायालय हैं, चाहे वे हाई कोट्र्स हैं और चाहे वह सुप्रीम कोर्ट है,

वहां उनकी कोई जगह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार बताने का काम करे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कितने-कितने लोग, वीकर सैक्शन, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ट कास्ट्स के हैं? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान के संविधान में देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऊपर उठाने के लिए जो अवसर मिला यानी नौकरियों में जो आरक्षण मिला, वह देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें अभी तक लागू नहीं हुआ है। किसी भी कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक में भी आरक्षण नहीं है। जो लोग सदियों से दबे-कुचले और पिछड़े हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जो देश के लोगों को न्याय देते हैं, वह न्याय की संस्था अपने संविधान के साथ अन्याय करती है।

(2Q/पीएसवी पर जारी)

PSV-PK/2Q/3.10

श्री शरद यादव (क्रमागत): इस सदन में एक बार नहीं, कई बार यहाँ के लोगों ने इस सवाल को उठाने का काम किया है। एक दिन भी सरकार इसकी तरफ सचेत नहीं होती। वह सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहती? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संविधान के दायरे के बाहर नहीं हैं। क्यों उन्होंने हर जगह रिजर्वेशन नहीं रखा है? जब वे वहाँ रिजर्वेशन नहीं देते, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ कई बार-- हिन्दुस्तान की समाज-व्यवस्था के बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं हैं और कुछ लोग अपने जन्म के साथ जुड़े रहते हैं। ये जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये हिन्दुस्तान की एक-

चौथाई आबादी हैं। इस एक-चौथाई आबादी के बारे में, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वे अपने नीचे अपने यहाँ जो भर्ती करते हैं, उसमें न्याय नहीं करते हैं। तो वे इसका जो भी सवाल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में दलितों के और आदिवासियों के हक़ मिलें, उनको गिराने का, उनको हमेशा खत्म करने का निरन्तर प्रयास करते हैं। क्रीमी लेयर संविधान के अन्दर कैसे आएगी? यह सदन उसको कभी नहीं हटाता है। यदि उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दी है, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं? यानी क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, जैसे अभी 50 लड़के पास हो गए, वे कंपीट कर गए हैं, लेकिन बैकलॉग इतना बड़ा है कि इसकी आप कोई इंतिहा नहीं देख सकते। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं सामने रखता। बैकलॉग इतना है कि कई डिपार्टमेंट्स, कई क्षेत्र तो भर्ती ही नहीं करते हैं। बैकलॉग इतना बड़ा है और सरकार यह कह रही है कि हम देश बना रहे हैं! यह जो राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो जो इतनी बड़ी आबादी है, जो दो-तिहाई लोग हैं, हिन्दुस्तान के 80 फीसदी लोग हैं, जोकि किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये 80 फीसदी हैं, अगर वे बलशाली नहीं होंगे, वे ताकतवर नहीं होंगे, तो यह देश कैसे मज़बूत हो जाएगा, यह कैसे ताकतवर हो जाएगा? क्या उनके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चिन्ता है? क्या इसमें बैकलॉग के बारे में कोई बात है? कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या आपने कोई बात कही है? मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कुछ नौजवान, कुछ लोग इसमें काम करते हैं। आरटीआई का एक एक्टिविस्ट राजनारायण है। वह इसका काम करता है। एम्स में उसको कहा गया है कि वह आ ही नहीं सकता है। उस पर कई तरह के गलत केसेज़ चलाए जा रहे हैं। यानी न्याय के लिए लड़ाई लड़ना भी मुश्किल है, यह हालत है।

मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए, इस सदन में सच्चाई को रखने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हालत, हाई कोर्ट की हालत मैंने आपको बताई कि हिन्दुस्तान के जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, किसी भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको न्याय कैसे मिल सकता है, जो अपने यहाँ न्याय नहीं करते हैं? वह न्याय, जो संविधान में दिया हुआ है, उस संविधान के न्याय को जो लोग बराबर काटने-छाँटने का काम करते हैं, उन्होंने संविधान के विपरीत यह क्रीमी लेयर लगायी है। सदन के पास ताकत है, सरकार के पास ताकत है, तो क्यों नहीं इसे बढ़ाते हैं? आज तो चपरासी की भी तनख्वाह बहुत बड़ी है। तो जिसके पास साधन नहीं होगा, यह जज करने का मामला है, सम्मान का मामला है। यह पैसे का मामला नहीं है, एक तरह की जो सामाजिक विषमता है, उसमें जो इज्ज़त और मान-सम्मान का सब तरह से शोषण हो जाता है, वह उसकी बाबत है। मैं आपको निवेदन करूँगा कि भारत के जो कॉलेजेज़ हैं, उनमें लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो 100 फीसदी लोग हैं, उनमें से सिर्फ एससी के 7 परसेंट लोग हैं और एसटी के 2 परसेंट हैं। वहाँ हज़ारों, लाखों पोस्ट्स हैं। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वाइस चांसलर्स कितने हैं- शैड्यूल्ड कास्ट्स के ज़ीरो हैं और आदिवासी कितने हैं? अभी अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटी बनी, उसमें एक आदमी रखा गया है। तो बताइए कि देश कैसे बनेगा? बताइए कि यह कैसे मज़बूत बनेगा, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वह कैसे मज़बूत और मज़बूत होगा? ये कौन हैं, मुट्ठी भर लोग हैं।

(2आर/वीएनके पर जारी)

श्री शरद यादव (क्रमागत) : अब ये तंत्र जो चलाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मुणगेकर जी और पी. एल. पुनिया जी ने यहां जो सवाल पूछा है, मैं उनके सवाल का जवाब यहां दे रहा हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ, इस सरकार का जवाब है, यहां पर जो दलित लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, उसी पर मैं कहना चाहता हूँ। इस सरकार में जितने सचिव हैं, एससी, एसटी और ओबीसी.... मैं मानता हूँ ओबीसी के लिए प्रमोशन में जो रिजर्वेशन हुआ है, उसमें इतने समय में उतने लोग नहीं आ पाए, जो प्रमोशन वाला है। 70 सेक्रेटरीज़ हैं, उनमें एससी के 3 हैं, एसटी के 3 हैं और मैं आपसे यह कहूं कि जो असली ट्राइबल हैं, वे ये नहीं हैं। ज्यादा लोग नॉर्थ-ईस्ट के और राजस्थान में मीणा लोग हैं, वे इसमें ज्यादा compete करते हैं। ये जो असली आदिवासी हैं, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज में बसे हुए लोग हैं, उनका एक भी आदमी इसमें कहीं नहीं है। संयुक्त सचिव 278 हैं, इनमें से 24 एससी के हैं, 10 एसटी के हैं और 10 ओबीसी के हैं। मैंने कहा कि सचिव में एक भी ओबीसी का नहीं है। जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है, तब से एक भी ओबीसी नहीं है। उसके पहले के जो लोग हैं, वे एक-दो हैं, जो मुझसे मिले भी हैं। अब यह तंत्र है! ऐसे में आप कैसे नोटबंदी को नीचे तक ले जा सकते हैं? यह जो आपका तंत्र है, उस पर मैं आगे आऊंगा।

सरकारी बैंकों में जनरल मैनेजर के 436 पद हैं और उनमें से 5 ओबीसी के हैं, 14 एससी के हैं, 7 एसटी के हैं। 436 में से 26 हैं। हमारे सरकारी बैंकों में यह हालत है। सरकारी बैंकों में कुल 1,216 डिप्टी मैनेजर हैं और उनमें 14 ओबीसी के हैं, एससी के 72 हैं, एसटी तो सबसे नीचे है। मैं आपसे कहूं, मेरी चुनौती है कि सरकार सर्वे करा ले,

विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो आदिवासी रहते हैं, उनमें से एक भी नहीं है, जो है, वह ओडिशा का है, वह मध्य प्रदेश का है, वह छत्तीसगढ़ का है या गुजरात का है। मैं यह चुनौती देता हूँ कि आप आईएएस में यहां के एसटी के दो या तीन ऑफिसर्स भी बता देंगे, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। इनको नहीं मिलता है, इनकी जगह ट्राइबल्स के नाम पर दूसरे लोगों को मिलता है। इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सोचने को तैयार नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम लोग भी इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानते हैं। मैं कई बार उसमें गया हूँ। उसमें जो 100 प्रोफेसर्स हैं, उनमें से एससी के सिर्फ 9 हैं, एसटी का ज़ीरो है और ओबीसी का ज़ीरो है। यह जो 80 फीसदी आबादी है, यह इससे नदारद है। जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, हिन्दुस्तान में लोग जिस यूनिवर्सिटी को बहस के लिए, तमाम चीजों के लिए मोहब्बत करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सपनों के साथ जिस यूनिवर्सिटी को बनाया था, उसमें यह हालत है।

(2एस/एनकेआर-एसकेसी पर जारी)

NKR-SKC/2S/3.20

श्री शरद यादव (क्रमागत) : यदि दूसरे आंकड़े मैं दूंगा, तो उसमें काफी समय चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हालत मैंने आपको बताई। देश में जो सोशल डिस्पैरिटी है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि सबसे ज्यादा, सबसे गम्भीर सवाल जो है, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में थोड़ी-थोड़ी करके सब चीजें हैं, जैसे हर साल रहती हैं, वही इस सरकार के समय में हैं, उसमे कोई नई बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : शरद जी, संक्षेप में कहिए। समय समाप्त हो रहा है।

श्री शरद यादव : इसमें सबको साथ लिया गया है। रेल बजट है, जनशक्ति है, स्वच्छ भारत मिशन है, एल.पी.जी. के 2.2 करोड़ हैं यानी सब तरह के आर्थिक और इकोनॉमिक मामलों का वर्णन है, लेकिन जो सोशल डिस्पैरिटी, जो सामाजिक विषमता है जो आर्थिक विषमता की महतारी है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता और आज नहीं तो कल यहां बगावत होगी। ये भी इंसानों की संतानें हैं, आज दुनिया बदली है, ये ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे, ऐसे ही नहीं देखते रहेंगे। उस सदन में तो संख्या ज्यादा है और एक तरह से उसमें संतुलन भी है लेकिन यहां रिजर्वेशन नहीं है। यहां संतुलन नहीं है।

मैं, अंत में, इस सदन में यही कहूंगा कि जब संविधान सभा का समापन हो गया और बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ, उस दिन उन्होंने जो चेतावनी दी थी, जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा था कि देश को सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी से लड़ाई लड़नी होगी। एक-तरफा आर्थिक मामले में तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सामाजिक मामले में बिल्कुल हम सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं और न हमारा हृदय बोलता है। जो हमारा पूरा तंत्र है, संसद भवन की इमारत इस बात की गवाह है, उन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी के रहते भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर गैर-बराबरी खत्म नहीं की गई तो व्यवस्था से नाराज लोग पूरे संवैधानिक ढांचे को चरमरा देंगे, गिरा देंगे।

अंत में..(व्यवधान).. मैं समझ गया और बैठना चाहता हूं और अंत में यही कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सारी चीजें हैं, विशेषकर नोटबंदी के मामले में पूरे सदन में हर मैम्बर ने जो बोला, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के चलते पूरे देश में जितनी तरह के दलाल पैदा हुए, वैसे हालात कभी पहले इस देश में नहीं हुए। पहले दिन से लोग हजार रुपए के 800 रुपए ले लो, फिर आया कि हजार रुपए के 900 रुपए ले लो, यहां से वहां तक आपका जो तंत्र है, वह तंत्र न्यायसंगत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तंत्र में सब तरह के लोग हैं। भारतीय समाज के हर हिस्से के लोग होते तो आपकी नोटबंदी के माध्यम से आप जैसा चाहते थे, जो करना चाहते थे, उसका कुछ परिणाम निकलता। लेकिन उसमें इसलिए कुछ नहीं निकला क्योंकि आपका जो तंत्र है, वह किसी भी चीज के लिए तैयार ही नहीं था। जितनी तरह के प्रोग्राम आपने दिए, वे सभी इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आपका तंत्र नीचे तक बेईमान है। इंदिरा आवास से लेकर हर तरह की जितनी भी सुविधाएं आप देते हैं, कोई न कोई रास्ता वह निकाल लेता है। जिन लोगों से आपका तंत्र बना हुआ है, उनका मन उन्हें वहीं बनाए रखने के लिए, हिन्दुस्तान की बड़ी आबादी को दबाए रखने के लिए, शोषित रखने के लिए, उनकी इज्ज़त, मान-सम्मान, सम्पत्ति, सम्पदा सब चीजों का शोषण करके, उन्हें फिर से वहीं का वहीं रखने के लिए काम करता रहता है।

2T/DS/पर जारी

श्री शरद यादव (क्रमागत) : इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह विनती है कि यह अभिभाषण अधूरा है, यह अभिभाषण पूरी तरह से अधूरा है, हिन्दुस्तान को बनाने वाला नहीं है। अगर हिन्दुस्तान को बनाना है, तो हिन्दुस्तान की जो 80 फीसदी आबादी है, जिसको संविधान ने थोड़ा-बहुत जो हिस्सा दिया है, उस हिस्से पर हर अभिभाषण में हमें पूरा ध्यान देना होगा। यह पहली बात हुई।

दूसरी बात यह कि पूरे देश में जो लूट है, अगर उसको रोकना है, तो इसके लिए सबको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(समाप्त)

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष जी, चूँकि अभी शरद यादव जी हिन्दी में बोले, इसलिए मैं अंग्रेज़ी में बोल लेता हूँ।

Sir, all of us know that the hon. President delivers an Address conventionally to the Parliament every year, which is a script that is approved by the Cabinet, and he just reads out that script. Normally, the hon. President is very fond of using four 'Ds' to describe the Parliamentary democracy in our country. He often says that there should be debate, discussion and then a decision, and not disruption. That is his very fond philosophy. Four 'Ds' is what he uses. But, unfortunately, the irony is that he read out a speech in which there are also four 'Ds', but these are not the 'Ds' that he is fond of, and these four 'Ds' are - ***** which are leading up to a

* being unfolded. So, I would like to dwell on these four 'Ds' that are contained in this rather long

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

80-paragraph Address that the hon. President has delivered. But before I come to the content of this hon. President's Speech, Sir, let me refer to the fact there have been two references that are made to very eminent and very influential personalities of Indian culture and history. One is to the saint-philosopher, Ramanujacharya. The reason I think I should just refer to this is the fact that Ramanujacharya is one of those personalities whose philosophy laid the foundations for the Bhakti Movement in our country, a philosophy where he replaced the devotion to rituals as a devotion to God for the realization of spiritual fulfillment. And, what does he say? He says, "Discursive thought is necessary in humanity search." Please note, "Discursive thought is necessary in humanity search for ultimate verities." Now, he shows his God as Vishnu and the King of the Chola Empire then was a King called Kulottunga. He banished Ramanujacharya because Kulottunga was the King and the official religion was Shaivism, while he chose Vishnu and, therefore, Vaishnavism. Sir, banishing that thing is an important point which must be noted in the background of his own philosophy that because of a certain belief of yours, you are banished from that Kingdom. What we are seeing today in our country is precisely that - if you do not believe in my God, then you are not part of India. And, if that is the sort of an invocation that you are doing, Ramanujacharya is not the person

whom the President of India had to refer to; it should have been Kulottunga because that is exactly the atmosphere that is being built up in our country today. That is the first point of first 'D' that I was talking of deception. The second…(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: The CPM leader…(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, Mr. Jairam Ramesh is always over-awed and disappointed with CPM leaders' invokes, but remember, a CPM leader is a Communist who believes that all that we have today is the product of human labour. (Contd. by 2U - GSP)

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): And that human labour is my labour, and, that is why, I am a Communist. All this is my heritage, Sir. So, I also have the right to invoke this.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Jai 'ram' and Sita 'ram' !

SHRI SITARAM YECHURY: That is again an irony. …(Interruptions)… Hon. Minister, Ravi Shankar ji, has actually pointed out a very correct fact that all

the 'rams' are here in the Opposition, no one is there. …(Interruptions)… There is not one 'ram'.

SHRI JAIRAM RAMESH: There is one ram, 'Ramlala'. …(Interruptions)…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): One 'ram' is coming. …(Interruptions)… One 'ram' is coming.

SHRI SITARAM YECHURY: I come to my second point which is about Guru Gobind Singh. Sir, Guru Gobind Singh is one of the most venerable leaders of the Sikh religion, the Sikh panth of India for what he contributed. All of us know this. Remember, Sir, he was the one who founded the *khalsa panth* at Anandpur Sahib. He founded the *khalsa vani*, and, the slogan that he gave is, "Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh."

On the basis of that slogan of the *khalsa panth*, he finalized the Guru Granth Sahib and said that is the eternal guru, with no more guru to come. The whole thing that he established was based on five Ks. What are these five Ks? These are, Kesh, Kara, Kangha, Kechera and Kirpan.

All of us know this history, and, if some do not know it, I would only beseech them to try and understand this history because it is a very important development in Indian philosophy and history. As far as the 'kirpan' is concerned, he was asked as to why he was giving the kirpan. What was his answer, Sir? He said, and, I am quoting, "To defend himself

and the poor, the weak and the oppressed from all religions, castes and creeds." To defend the *khalsa panth*, to defend the humanity from all forms of religious oppression, all forms of caste oppression, all forms of oppression that we find in this country, the kirpan is one of the necessities of a *khalsa*.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Now, today, what do we have in our country? Again, therefore, I say, it is an irony why Guru Gobind Singh has been invoked. While the *kirpan* was meant to defend the poor and the oppressed from religious persecution, to defend the poor and the oppressed from caste persecution, instead, Sir, in the line up to the Uttar Pradesh Assembly elections, we heard a new announcement now that they will have these Anti-Romeo Squads. I will come to that point later. Instead of protecting the oppressed, this is being talked about. I will come to the point of these squads later. You just heard my senior friend, Sharad Yadav, speaking about what has been happening to the *dalits*, tribals and to the *OBCs*. Instead of protecting the oppressed, what we have, on the contrary, is that during the course of last year, the President dwelt it in his balance sheet of his Government's work, there have been greater atrocities only. It is not protection. It has been greater atrocities with official patronage, which is happening in our country. That

is why, once again, invoking Guru Gobind Singh is very, very ominous and does not completely match with what has been the experience of the country in the last one year. That is why, Sir, I say that these two invocations are not merely ironic but are part of the philosophy of deception that this Government has been practicing.

Now, I come to the second 'D' that I was talking about, which is disruption. What we have seen in the course of one year, not only with this demonetization which, of course, is the biggest disruption that has happened to our country, to our life, to our economy. It has actually disrupted the normal existence of a vast majority of our people and their day-to-day livelihood. We have been through this debate earlier, Sir. Today, with all the points that were made earlier in the debate, what I myself had made here, I can only say that none of the four points that the hon. Prime Minister cited as reasons for this demonetization were achievable then, and, now, practically, we see that they have not been achieved, and, on the contrary, many things have actually been endorsed and legalized.

(Contd. by SK-2W)

SK-SC/2W/3.35

SHRI SITARAM YECHURY (contd.): Why do I say this? There is more money than what was demonetized that is coming into your banks today. What does that mean? It means that all the black money that was held as stock in the country has now been converted into white. All the illicit, counterfeit money that you have in our country has been legalized. Now, what was the objective? You said that will reduce terrorism, terrorist funding. After your surgical strike, the number of our *jawans*, who are sacrificing their lives to defend us, while we are proud of them and we salute them, the number of them who lost their lives in terrorist attacks has doubled in these three months compared to earlier three months. And about corruption, we have just heard Mr. Sharad Yadav telling us about the levels of corruption. Now the common denominator for corruption transactions has been increased from one thousand rupees to two thousand rupees. So, the rate has only doubled. ..(Interruptions).. Like he says, there have been so many intermediaries. None of these have got finished, but in the process, there is agony of the people. There is not a mention of more than a hundred people who died wanting to withdraw their own money. The Constitution of India, Sir, today gives the right to property. The money in the banks is individual's property. That right has been violated by

this, and those who wanted to exercise that right have lost their lives, but there is not one mention about that. Outside, there are references saying when a big *yagya* takes place, "जब एक बड़ा यज्ञ होता है तो आहुति होती है।" You sacrifice for the sake of a big *yagya*. So, these innocent peoples' deaths are brushed aside as sacrifice of people for something big that is being achieved, and what is that that you have achieved, Sir? When I say 'disruption', it is actually leading up to destruction, if you are not taking up some concrete, countervailing action now. Forty-five per cent of our GDP is contributed by what is called the informal economy. Nearly eighty per cent of our employment is generated in that informal economy, and that informal economy is almost hundred per cent on the basis of cash transactions. All that has been disrupted. Crores of Indian people have been put to unnecessary suffering as a result of this. And we have seen the assessments that were made. We ourselves have said how the international agencies have said the impact of that will be on our GDP. Our former Prime Minister, former Finance Minister and former Governor of the Reserve Bank -- I think there is only one individual in the whole of India who has served in those three capacities -- has said, with all that wisdom, that it will fall the GDP at least two percentage points. Forget the veracity of what you want to do, the fact is that there is an economic slowdown. Even the Government's

own Economic Survey recognises that. In formal sector, your retail trade has fallen in the first two months. As much as 75 per cent is the fall of your retail trade. I have personally witnessed, we all witnessed in Delhi, farmers coming from nearby with onions in their tractors and trailers and selling them at ten rupees a kilo, and some of them dumping. In Raipur, I was there for a meeting, and we had the farmers coming and distributing tomatoes free. I had to ask one of them, "Why are you distributing it free?" He said, "If I want to destroy it, I will spend more money. So, it is better that I go and give it free." The farmers, where the harvesting has been done, are selling their harvest, their crop, for one half of the Minimum Support Price. Nobody is there to procure it because there is no cash to give to the farmers. So, the farmers are selling their produce at one half of the Minimum Support Price. This is the case with the fishermen too. You come from a State, Sir, where a substantial contribution to the economy is made by the fishermen. Now, without cash transactions, you know what happens to the fish they

catch. Their family can't survive the day. The fish will rot, and the entire consequential multiplier effects will take place in the economy.

(Contd. by YSR/2X)

-SK/YSR-GS/3.40/2X

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): I am only giving you some of the examples. This is happening to your informal sector. In agriculture, there is reverse migration of agricultural labour from Punjab and Haryana in the peak season, because they can't employ them.

Then what is happening to manufacturing in industries? Every sector in the manufacturing industry has shown a drop in sales and production. In the case of two-wheelers, it is dropped by thirty-five per cent in these three months of demonetisation. The Prime Minister's constituency is famous for *Banarasi sarees*. They are being sold at half the price today because people are not coming to place the contract for those *sarees*. And I will tell you what is worse, Sir. The Prime Minister either yesterday or day before yesterday was in Meerut. He was talking about sports material being produced in Meerut. He said, "With your sports material, our country gets laurels in all the international sports events." And what is the report from there, Sir? Twenty per cent business is down in the sports goods industry. Half the workers have been laid off. I can go on mentioning it. I have got a

list of all the sectors that are there in the country which are badly affected. And what is the net result of this? A massive surge in unemployment. Last year, it was admitted here in an answer to a parliamentary question that the eight core industries in 2015 generated only 1.35 lakh crore jobs. Now the Labour Bureau tells us that there are 55,000 jobs in these eight core industries. Leave alone the informal economy; this is the formal organised economy. This is what is happening. And it is on the basis of this that the Economic Survey had said that in order to get out of this impact of demonetisation what is required is to vastly expand our domestic demand. It means you have to vastly expand the purchasing power of our people. It means you have to vastly expand public investment. This is the recommendation of the Economic Survey. And what does the Budget do? Instead of expansion, it contracts the Indian economy. Just look at these telling figures. The size of the Budget is a contraction from last year's Budget – from 13.4 per cent of our GDP to 12.7 per cent. The Budget itself is contracted as a proportion of the GDP. Then what is the capital expenditure? It has come down from 1.86 per cent of the GDP to 1.84 per cent this year. I am giving you the figure in terms of percentage of GDP, because that is not merely informative but more accurate in order to understand it. Then an announcement was made that you are giving so

much of allocation to various projects. MGNREGA was one of the projects. You have said that it is the highest ever allocated by any Government for MGNREGA! You announced that its allocation is Rs.48,000 crore. It is Rs.600 crore more than what was spent last year which is Rs.47,400 crore. So, what is this great boost that you are talking about for giving employment? Even allocation for agriculture as a percentage of GDP has come down from 1.98 per cent to 1.95 per cent. Remember, Sir, one percentage point of GDP is about one and a half lakh crore of rupees. Am I right? I am taking Mr. Chidambaram's approval because he is an authority on this. So, a reduction of three points in the GDP means a huge amount of money. This is what is happening with the economy. On the other hand, what have you done? The Economic Survey says, "Expand the purchasing power and domestic demand." You have decreased your revenue from direct taxes by Rs.20,000 crore which means relief to the rich. You have increased your indirect tax collection by Rs.75,000 crore which is a greater burden on the consumer, the common man.

(Contd. by VKK/2Y)

-YSR/VKK/2Y/3.45

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): So, instead of having a greater disposable income to buy something so that our demand can expand, this

whole Budget is contracting your domestic demand further, which means keeping greater miseries on top of demonetisation that you have brought about. So, this is where the disruption of the economic story of India is actually happening. And if this is happening, there is one element of this, which Mr. Sharad Yadav has spoken out in detail and I am not repeating it. But, I must refer to it because this is really telling. The other day the hon. Prime Minister spoke that his and his party's fight in Uttar Pradesh is against what he calls SCAM. He was referring to political parties. It is SCAM. But, what he is doing to the country is actually fighting against a SCAM in which S, C, A and M mean different things. SC stands for scheduled categories and M for minorities. This is a battle that the Prime Minister and this Government is conducting against SCAM. This is against SC, ST and minorities. Look at the Budgetary allocations. 1.48 per cent of the Budget, not of the GDP, has been allocated for SC programmes. It is 1.48 per cent. Then, 2.44 per cent is what has been allocated for ST development. For minority welfare, there is only a mention of various things but there is no substantial increase in terms of the recommendations of Sachar Committee, Ranganath Mishra Committee, etc. None of them is going to see the light of the day.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): It is Rs.400 crore. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am sorry. The hon. Minister intervened. So, I yielded for that. Naqvi Saheb, I also understand your emotional sentiments concerning this issue. But, what has been allocated is no way near to what is required to implement the recommendations. Sir, for women, what is the allocation? All these are Budget figures. For women, it is only 5.3 per cent. Fifty per cent of our population is women. So, what are we doing? It is a demographic dividend which should be an asset for our country. Already, two-thirds of our country is below the age of 40. Till 2020, this will increase further. Instead of converting that into an asset by providing them with education, jobs and health, we are converting them into a liability that will be a millstone on the whole country and it is something that is completely unacceptable. And that is exactly what these policies are leading up to. Then, you take a moral posture of electoral funding. It says, "reduced from Rs.20,000 to Rs.2,000". So, I will give you ten more names for the same amount of Rs.20,000. That's all you want. Whom are we fooling, Sir? …(Interruptions)… Sir, please tell me that. Let the Prime Minister and the BJP President explain that in one rally, where they claim ten lakh people

came. Officially, the party claims that they hired ten thousand buses apart from helicopters and various other things. Where did the money come from? You don't know; I don't know because there is no ceiling on the expenditure of political parties. You have ceiling on expenditure of candidates. But, political parties can spend as much as they can and finally, you give an account. You file a return saying that this is the thing. That's it. So, if you really want to curb political corruption, then, bring the expenditure of political parties under a ceiling. Why are you not? Why are you resisting that? If you really want to curb political corruption, ban corporate funding to political parties directly. Let the corporates fund and they should fund. If necessary, bring forward a law. Like CSR, bring forward a law for a fund for democracy. Let them fund and let that fund be administered by the Election Commission or the Government and put it in place for State funding of elections. We have discussed that a number of times in our electoral reform agenda. Right from Indrajit Gupta Committee Report downwards, we have been discussing this. Many countries in the world practise State funding. So, do that. Unless you take such measures, there is no way you can stop the influence of money power and you are only paying lip service and moralistic rituals. All this is meaningless.

(Contd. by BHS/2Z)

-VKK/BHS-ASC/2Z/3.50

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): Therefore, this is, eventually, leading up to a situation where this disserving of our economy is only going to make matters worse regarding one aspect, that is, widening inequalities. In 2004, when this Government assumed office, 1 per cent of Indian people held 49 per cent of our GDP. One per cent! Today, that 1 per cent, in 2016, holds 58.4 per cent of our GDP. That is merely a 10 per cent jump in the incomes and wealth of the rich, and the immiserization and wreckage of the lives of the poor! That is what this trajectory is and that is why I say that this is a major disruption that has been caused in our country by them. But why this demonetization now if all the objectives have failed? It is very clear now, shift to a digital economy, where every digital transaction carries a cost. That cost is a bonanza for profit maximization of your foreign capital and also your Indian capital. A one hundred rupee note, if it travels a lakh transactions, the value of that hundred rupee note will still remain hundred rupees. But if these lakh transactions are done through digital medium with a 2 per cent charge for every transaction or even a 1 per cent charge for every transaction -- it is now 2.5, I think -- so if you take 2.5 per cent for every transaction, a one hundred rupee note transacting one lakh times would mean a profit of 2.5 lakh rupees. Value remains the same 'hundred

rupees'. So, what are you doing? Giving the bonanza of profit maximization for these companies, a bulk of which are foreign companies. Internationally, today, there are three major companies -- there may be some others -- who handle your credit card and debit card, that is, Visa, MasterCard and American Express. If these are the ones who are going to be benefitted out of this, what is the meaning of this? This, Sir, ties in with the reduction of India as a strategic ally, a subordinate strategic ally, of the United States of America. This is happening when Mr. Trump has become the President. The present Government seems to be very happy. I mean, it's fine, we wish. Anybody who wins an election, we wish them. That is the normal practice. But wishing them should not translate into being ecstatic about saying that, I mean, eagerly waiting when we will be invited to visit there. And what is he doing with our Indians, Sir? There are five lakh Indian students. Youth, not students, youth working, mainly, in IT sector who are there on H1B visas and whose existence there has become completely tenuous, a complete state of uncertainty. There is not one word from the Government saying that we will protect their interests. Our Indian-born people there are being harassed and you see reports everyday somebody being picked up and taken up for questioning. It is apart from everything else that is happening in the United States of America. Now, if that is

happening to us Indians, your status of a subordinate ally of that USA -- joined naval exercises in South China Sea along with USA and Japan -- what is the signal you are giving to the world? That you are today a junior partner of USA in terms of containment and in terms of their hegemony over the Asia-Pacific Region. Is that in our country's interest? Now, these are issues that are coming up and if this is actually happening in order to save our banks, the banks have become vulnerable because of loot that has happened through the NPAs. If you add the interest today, the existing NPAs amount to Rs. 11 lakh crores. Rs. 11 lakh crores! What have we done through demonetization? You have withdrawn about Rs.15 lakh crores of rupees and you have injected around Rs.5 lakh crores of new notes.

(Contd. by DC/3A)

-BHS/DC-LP/3.55/3A

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): So what have you done? You have given ten lakh crores of rupees to the banks as their cash surpluses. The banks that were collapsing because of these NPAs, through demonetization, they are now standing on their feet. Then what did you do? Those, who looted the banks, are going away scot free. We have been asking since time immemorial. If, say, small farmers do not pay back their loans, you get after them. If they don't return the loan, you confiscate their

cattle; you confiscate their properties, their land. But when the big fish don't return the money, there is no way of confiscating their properties. Now, they have said, "If they go abroad, we will do something." So, now you are giving them an incentive. "You please go abroad, and then we will see as to what can be done." …(Interruptions)… Sir, please bear with me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Try to conclude also.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, in the last Session, it was announced that Rs. 1.12 lakh crore of NPAs have been waived off. The former Finance Minister is here. Rs. 78,000 crores is what he waived for the farmers then, about ten years ago. Your farmers' rate of suicide has gone up by 26 per cent. By demonetization, they are, today, totally burdened with this debt of theirs. Waive those loans for the welfare and prosperity of India rather than the loans of the rich, who have but they don't pay back the banks, which is your money, my money. What is happening today in India, Sir? Is it not that when the banks are collapsing, there is a bailout package that is announced by the USA and all other Western countries? In India, today, what you are doing is a bail in package. You are making common people not to withdraw their own money from the banks and, thereby, bailout the banks and, thereby, even exonerate those who have looted the banks. That is why, Sir, this is a very serious matter, and I am very disappointed that the hon.

President's speech does not reflect any of this reality. On the contrary, I have gone through this whole thing very meticulously. There are twelve, about one dozen *Pradhan Mantri Yojanas* that have been listed, from last year to this year. Shall I read them out, Sir? It will be an interesting compilation for everybody. These are, *Pradhan Mantri Mudra Yojana*, *Pradhan Mantri Aawas Yojana, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadi Pariyojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri YUVA Yojana, Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana,* ...(Interruptions)...नहीं, नहीं, ग्यारहवीं, *Pradhan Mantri Urja Ganga Yojana,* then the twelfth, *Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana*. इसमें उन्होंने 12 गिनाई हैं। इसके आधार पर वे कह रहे हैं हम देश की बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमने इन सब पर अमेंडमेंट्स मूव किए हैं। जो गुजर गए हैं, उनके बारे में जिक्र भी न करना, उनके लिए मुआवजा देना, वह बात छोड़िएगा, लेकिन finally, the last point that I want to come to is, all these three D's i.e., deception, disruption and diversion should not lead up to a fourth 'D', like the hon. President used to remind us that debate, discussion and decision of Parliamentary procedure should not lead to disruption. These three should not lead to the fourth 'D', which is the diabolic agenda that is being unfolded and that is of serious concern for me and I think for you, for the entire august House and for

the country also. As I have mentioned earlier, you have now the announcement of anti-romeo squads. You have the cow protection squads, cow protection vigilantism, which has claimed the lives of Dalits in Una; which have claimed the lives of two youths who were hanged to death when they were taking their cattle to a fair in Latehar in Jharkhand; which has claimed the death of Akhlaq, who was lynched in Dadri on the allegation of storing beef.

(Contd. by KR/3B)